



हर बार जब मैं एक बच्चे को
मुक्त करता हूं मुझे लगता है
ये भगवान के कुछ करीब है।

-कैलाश सत्यार्थी



सांध्य दैनिक 4PM

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork [@Editor_Sanjay](https://www.youtube.com/@4pmNEWSNETWORK)

• तर्फः 10 • अंकः 179 • पृष्ठः 8 • लेखनक, शनिवार, 3 अगस्त, 2024

इंडिया-श्रीलंका का पहला वनडे बराबरी... | 7 | जरूरत या राजनीति: जाति है जो... | 3 | क्रीमीलेयर की व्यवस्था जायज... | 2 |

जिद... सच की

अयोध्या मामले में गरमाई यूपी की सिपासत | भाजपा व सपा में मुद्दे को लेकर तीखी टकरार

विपक्ष बोला- पूरी जांघ के बाद दोषी पर हो एकरान

- » योगी सरकार ने शुरू की कार्रवाई
- » पूराकलंदर थानाध्यक्ष व भद्रसा चौकी इंचार्ज सर्पेंड
- 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। अयोध्या के भद्रसा क्षेत्र में गैंग रेप का शिकार हुई पीड़ित किशोरी के मामले में यूपी की सियासत गरमाई हुई है। चूंकि आरोपी सपा से जुड़ा हुआ है तो बीजपी भी सपा मुखिया पर हमलावर है। वहीं सपा ने भी कहा है अपराधी कोई भी हो अगर सबूत है तो उस पर कार्रवाई हो पर निर्दोष पर कार्रवाई अन्यथा होगा।

अयोध्या में 12 साल की बच्ची से कठित सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर भी सपा

और भाजपा के बीच जुशानी जंग जारी है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने विस में बोलते हुए कहा था कि गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों में से एक मोदी खान सपा सदस्य था, लेकिन पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उधर पीड़ित

पीड़िता की मां से सीएम योगी ने की मुलाकात



पीड़ित किशोरी को लेकर बीकाए प्रियांशु के विधायक अमित यौहान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए। पीड़ित के साथ शुभात से रही समाजसेवी मंजु निषाट भी साथ गई उनकी माने तो मुख्यमंत्री ने पहले पूरी घटना के बारे में पूछ लिया उन्होंने मुकदमा देव से दर्ज करने के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी नी पार्टी का आरणी ही उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई होगी। इसके साथ उन्होंने आर्थिक मदद देने के लिए भी निर्देश दिया।



सपा का मतलब गुंडागर्दी और अपराध को संरक्षण : केशव प्रसाद मौर्य

प्रदेश के उम्मीदवारी और भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार समाजवादी पार्टी प्रमुख अधिलेश यादव की आलोचना करते हुए उनकी पार्टी पर सुशासन और विकास को कामन रखने के बजाय गुंडागर्दी को बढ़ावा देने और अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया। कांगड़ा के नोटर्स सपा प्रमुख अधिलेश यादव भले ही गुंडोंलाल जैसे सपाई देखे, लेकिन ये किसी हालात ने नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि 2027 में रोपे जाने वाले विधायक युवाओं ने बीजों का प्रतीक कमल दिया रखा।

किशोरी की मां से सीएम से मुलाकात के बाद पुलिस और प्रशासनिक तंत्र हरकत में आ गया। चौकी इंचार्ज और थानाध्यक्ष

सपा प्रमुख अधिलेश यादव कब बोलेंगे : संजय निषाट

रायपी सरकार के मंत्री डॉ. संजय निषाट ने शनिवार को जिला नगिला अध्यक्षता में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। बाद निकल कर नीडिया से बात कर वह परिजनों का बाल बताते हुए पढ़े। उन्होंने सीएम योगी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने तरित कार्रवाई कर निषाट समाज को न्याय दिलाने का काम किया है। सपा अधिलेश यादव पर हमलाकार तोड़े हुए कह कि उनका पीड़ित का फॉर्मला सिर्फ दिखाया है। अब तक उन्होंने इस नामांके पर कोई बदलाव नहीं दिया है और न ही आरोपी नेता को पार्टी से निकाला है।

को सर्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोपी मोर्देंड की प्रॉपर्टी की जांच शुरू हो गई है।

बेकरी ढहाने बुलडोजर भी पहुंचा लहीं, शनिवार सुबह ही प्रशासन की टीम आरोपी सपा नेता गोर्ड खान की बेकरी ढहाने बुलडोजर लेकर पहुंच गई है। बेकरी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जुगू हैं। सवायत खान आयोग तक पहुंच दिया जाएगा। इस दैरान बेकरी में बन रहे खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इसके बाद बेकरी को सील कर दिया गया है। सवायत आयोग घोषित कर दिया गया है।

केवल आरोप लगाकर सियासत न की जाए : अधिलेश

कुक्कूर के मानाले में जिला पर भी आरोप लगा है उनका डीएनएटेस्ट कराया इसाफ का यत्न निकाला जाए न किए कराये डीएनएटेस्ट कराया इसाफ का यत्न निकाला जाए नी दोपी ने उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए लेकिन अब डीएनएटेस्ट के बाद आरोप झटे हुए कह कि उसका नामांके पर कोई बदलाव नहीं दिखाया है। अब तक उन्होंने इस नामांके पर कोई बदलाव नहीं दिया है और न ही आरोपी नेता को पार्टी से निकाला है।



फिर एकबार मणिपुर में भड़की हिंसा, चली गोलियाँ

- » मैतैई-हमार समुदाय में शांति समझौते के 24 घंटे के अंदर घरों में आगजनी
- 4पीएम न्यूज नेटवर्क

इंफाल। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर राज्य के जिरीबाम में शांति कायम करने को लेकर मैतैई और हमार समुदाय के बीच सहमति बनी। वहीं सहमति के 24 घंटे के भीतर जिरीबाम में हिंसा हो गई। यहां एक मैतैई बस्ती में गोलियाँ चलाई गईं। वहीं लालापानी गांव में एक घर में आग लगा दी गई। दरअसल मैतैई और हमार समुदाय के प्रतिनिधि मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले में हालात सुधारने और शांति बहाल करने के लिए साथ काम करने को सहमत हो रहे थे।

असम के कछार में गुरुवार को सीआरपीएफ सुविधा केंद्र में आयोजित



बैठक में आमने-सामने खड़े दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था। इसमें तय किया गया कि दोनों पक्ष सामान्य स्थिति लाने, आगजनी तथा गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। दोनों पक्ष जिले में तैनात सभी सुरक्षा बलों की मदद करेंगे। दोनों पक्ष नियंत्रित और समन्वित आवाजाही को सुविधाजनक बनाएंगे। सभी सहभागी समुदायों के प्रतिनिधियों ने इस दौरान वादों से जुड़ा बयान जारी किया। इस पर सभी के हस्ताक्षर थे। इस सहमति के 24 घंटे के अंदर

जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं

पिछले साल मई से इफाल घाटी के मैतैई और आसपास की पहाड़ियों पर दिखाने के बाल बताते हुए कहा गया है। और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। जातीय लूप से विधिधार्पूर्ण जिरीबाम इफाल घाटी और आसपास की पहाड़ियों में जातीय हिंसा से काफी हृत तक अस्तू था। हालांकि, इस साल जून में खेतों में एक किसान का क्षति-विकाश शर्त मिलने के बाद यहां भी हिंसा शुरू हो गई। दोनों पक्षों की ओर से कोई गंभीर आगजनी की घटनाओं के कारण हाजारों लोगों को अपने घर छोड़कर राहत दियी गयी जाना पड़ा।

जिरीबाम के लालापानी गांव में हिंसा हुई। गांव के एक घर में शुक्रवार रात हिंसारात लोगों ने आग लगा दी। साथ ही गांव को निशाना बनाकर कई रातंड गोले दागे और गोलियाँ भी चलाईं। घटना के बाद सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया।

यूपी के बरेली में बवाल तोड़फोड़ और आगजनी

बरेली के सिरोली थाना क्षेत्र के गांव दंतपुरा शिवगढ़ में युवती जिले गोर्ड खान की बेकरी ढहाने बुलडोजर लेकर पहुंच गई है। बेकरी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जुगू हैं। सवायत खान आयोग तक पहुंच दिया जाएगा। इसके बाद बेकरी को सील कर दिया गया है। सवायत आयोग घोषित कर दिया गया है। देखकर उसके परिवार वाले जिला बवाल कर दिया गया है। यहां तोड़फोड़ करने की जानी बढ़ी हुई है। इसके बाद उसके परिवारों ने गुस्सा लगाया है। लोग यहां नहीं थाने और पांच कर्मजे से सामान बाहर निकालकर पूरा मकान भी आग के हवाले कर दिया। तोड़फोड़ व आगजनी की स्थान पर पहुंची दायल 112 पुलिस नाकाशी साथी ढहाने हुई।



क्रीमीलेयर की व्यवस्था जायज नहीं : राजेंद्र चौधरी

आरक्षण के भीतर आरक्षण की पक्षधर नहीं सपा, ओबीसी कोटे में कोटा देने की मांग

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जातिजनजाति (एससी-एसटी) कोटे के भीतर कोटा वैधानिक ठहराने के बाद यूपी में ओबीसी आरक्षण के भीतर आरक्षण देने की मांग गरमा गई है। सपा व बसपा ने जहां इसका विरोध किया है वहीं कांग्रेस व भाजपा भीन है। हालांकि एनडीए के कुछ सहयोगी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हैं। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि एससी-एसटी के आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि सपा ओबीसी आरक्षण में किसी भी तरह के बंटवारे की पक्षधर नहीं है। हम क्रीमीलेयर की व्यवस्था को भी जायज नहीं मानते हैं।

एनडीए में शामिल

सुभासपा के महासचिव अरुण राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते

हुए कहा कि ओबीसी में भी आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। भाजपा एमएलसी व डॉ. अंबेडकर महासभा

ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने संपन्न दलितों से आरक्षण का लाभ न लेने का आह्वान किया है। अलबत्ता, बसपा आरक्षण के बंटवारे के पक्ष में

नहीं है। सपा भी ओबीसी आरक्षण में बंटवारे और क्रीमीलेयर की व्यवस्था के पहले से ही खिलाफ है। आरक्षण के भीतर आरक्षण के समर्थकों का कहना है कि ओबीसी आरक्षण का यादव और कुर्मियों ने अधिक कायदा लिया है। इसीलिए अब आति पिछड़ों पर अलग से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह से दलितों में वाल्मीकि, धानुक और डोम सरीखी जातियों को कम लाभ मिलने की बात समय-समय पर उठती रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स के माध्यम से कहा कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। क्या देश के खासकर करोड़ों दलित व अदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव से मुक्त आत्म सम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है। अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित?

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि एससी-एसटी वर्ग की जातियों का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। इससे समूह में पिछड़ी जातियों को लाभ मिलेगा। लेकिन एसी-एटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान न लाया जाए। अगर एसा किया गया तो हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी।

रिप्लिकन पार्टी ऑन इंडिया (अठावले) के प्रमुख और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने ओबीसी और सामान्य श्रीणि के सदस्यों के लिए भी समान उपवर्गीकरण की मांग की। अठावले ने कहा कि एससी-एसटी के लिए आरक्षण जाति पर आधारित है। एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान लागू करने के किसी भी कदम का आरपीआई (ए) कड़ा विरोध करेगी। अठावले ने कहा कि देश में 1,200 अनुसूचित जातियां हैं। इनमें से 59 महाराष्ट्र में हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत



महाराष्ट्र सरकार को अनुसूचित जातियों का अध्ययन करने और उन्हें ए, बी, सी, डी में उपवर्गीकृत करने के लिए एक आयोग बनाना चाहिए। इससे एससी में आने वाली सभी जातियों को न्याय मिलेगा।

बिहार को विशेष राज्य की मांग से जदयू ने किया किनारा

» 2025 में मिलेगा और बड़ा पैकेज : भगवान सिंह कुशवाहा

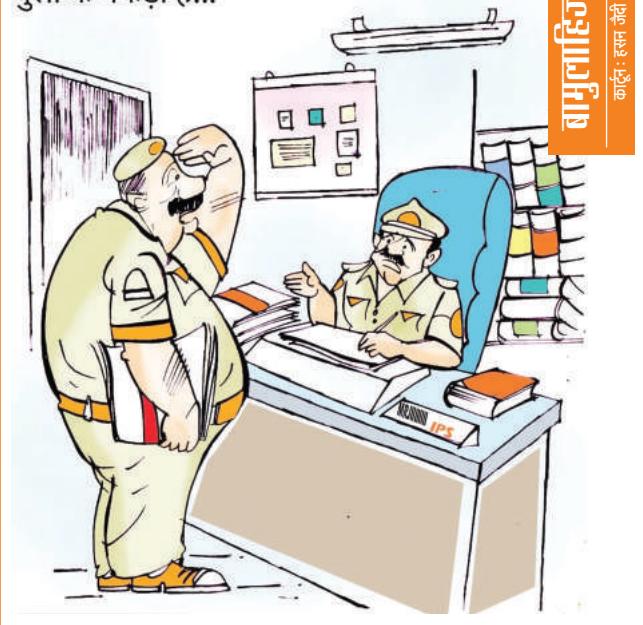
□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क



रहा है। भगवान कुशवाहा ने कहा कि हालांकि नीति आयोग में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उफ ललन सिंह हैं। अब अगर पार्टी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जबरदस्ती करेगी तो और भी राज्य मानक के विपरीत विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने लगेंगे। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में मानक बदलेंगे और अनुकूल स्थिति भी आएगी। उन्होंने कहा कि अभी जो केंद्रीय बजट में 59 हजार करोड़ का विशेष पैकेज मिला है, वह राज्य के केंद्रीय कर के 45 प्रतिशत हिस्से की अतिरिक्त राशि है। वहीं, जदयू नेता भगवान कुशवाहा ने दावा किया कि अभी यह विशेष पैकेज तो एक ज्ञांकी है। 2025 आने वीजिए, केंद्र से इतनी बड़ी राशि बिहार को मिलेगी, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं।

औरंगाबाद। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को जदयू ने फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पार्टी के बड़े नेता भी अब इस मांग से कठीनी काट रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधान पार्षद भगवान सिंह कुशवाहा ने विशेष राज्य की मांग पर कठीनी काटते हुए कहा कि बिहार विभाजन के पहले से पार्टी यह मांग करती रही है। उस वक्त राज्य की परिस्थितियां विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने लायक थीं, लेकिन कतिपय कारणों से यह मांग पूरी नहीं हो सकी। इसके बावजूद पार्टी की यह मांग बनी रही। पार्टी आज भी यह चाह रही है कि राज्य को विशेष दर्जा मिले, लेकिन बिहार अभी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के नीति आयोग के मानक पर फिट नहीं बैठते हैं।

साहब.... हमने चोरों को कभी दौड़ा के नहीं बुला के पकड़ा हैं...



नीतीश और मोदी सरकार पर भरोसा नहीं : तेजस्वी

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

पटना। 22 से 26 जुलाई तक बिहार विधानसभा का सत्र पहले से तथा था। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के सदस्य भी हैं और विपक्ष के नेता भी। पांच दिवसीय सत्र में वह गैरहाजिर रहे और नेतृत्व विहीन विपक्ष ने हर बात पर वाकआउट से जादा कुछ नहीं किया।

बाहर सरकार को घेरते रहने वाले तेजस्वी यादव सत्र के समय पटना आ भी गए तो अंतिम दोनों दिन उनका इंतजार ही होता रहा। अब तेजस्वी यादव पूरे एक हफ्ते बाद मीडिया के सामने आए और उसी बात से शुरुआत की, जिसपर विपक्ष ने विधानसभा को लंबे समय तक बाधित रखा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब राजद आरक्षण को लेकर सङ्केत से कोर्ट तक जाएगा। तेजस्वी ने कहा बिहार सरकार जातीय गणना करवाकर आरक्षण की सीमा को 75 प्रतिशत तक लेकर गई। इसके बाद भी हमलोगों को आंशका थी कि भाजपा के लोग किसी न किसी तरह से कोर्ट में अपने मुहरों को खड़ा करेंगे। लेकिन, कोई फायदा नहीं हुआ। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। हमलोग आरक्षण को अनुसूची 9 में डालने की मांग कर रहे थे। लेकिन, हमारी मांग पूरी नहीं हुई। इसीलिए हमलोगों ने अब केंद्र पर उत्तरने का फैसला लिया है।

**बोले-
अब हम
जाएंगे कोर्ट**

करवा आरक्षण को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। इसीलिए हमलोगों ने मांग रखी थी कि थी कि तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में आरक्षण व्यवस्था को शेंडूलूल नौ पर डाल जाए, ताकि इससे कोई छेड़खानी न हो। इसको लेकर हमलोग केंद्र सरकार से मिले थे। लेकिन, कोई फायदा नहीं हुआ। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। हमलोग आरक्षण को अनुसूची 9 में डालने की मांग कर रहे थे। लेकिन, हमारी मांग पूरी नहीं हुई। इसीलिए हमलोगों ने अब केंद्र पर उत्तरने का फैसला लिया है।

भाजपा सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है : इकरा हसन

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से सामाजिक पार्टी (सपा) की सांसद इकरा हसन चौधरी ने यूपी की योगी सरकार पर जोरदार हमला किया है। इकरा ने धर्मांतरण से जुड़े कानून में किए गए बदलाव पर बात करते हुए योगी सरकार पर कई सवाल खड़े किए।

इकरा हसन ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार सिर्फ धर्म की राजनीतिक करना जानती है, इसी तरीके से सिविल मैटर में जिस तरह से राज्य सरकार दखल दे रही है, वह लोकतांत्रिक ढाँचे को कमोजर करती है। इकरा ने कहा कि जब यह विषय समाज में पहले से है। हमारे क्षेत्र में भी इस तरह

के मामले हुए हैं और मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई भी हो रही है। जब कोई बालिग अपनी सहमति से संविधान में दिए अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें सरकार को दखल देने की जरूरत है ही नहीं। अगर कहीं फंसाकर या गलत तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है तो हमारे पास जो पहले से कानून हैं वो पर्याप्त हैं, लेकिन भाजपा धर्म की राजनीति की बजाए ऐसा कर रही है, कांवड़ यात्रा के दौरान इन्होंने नेम प्लेट लगाने का जो आदेश दिया था वो इसी के तहत था।

R3M EVENTS

ACTIVATION • EVENTS • EXHIBITION



R3M EVENTS

4/725 Vaibhav Khand, Gomti Nagar, Lucknow
E-mail: rajendra@r3mevents.com, Mob : 095406 11100

जरूरत या राजनीति: जाति है जो जाती नहीं!

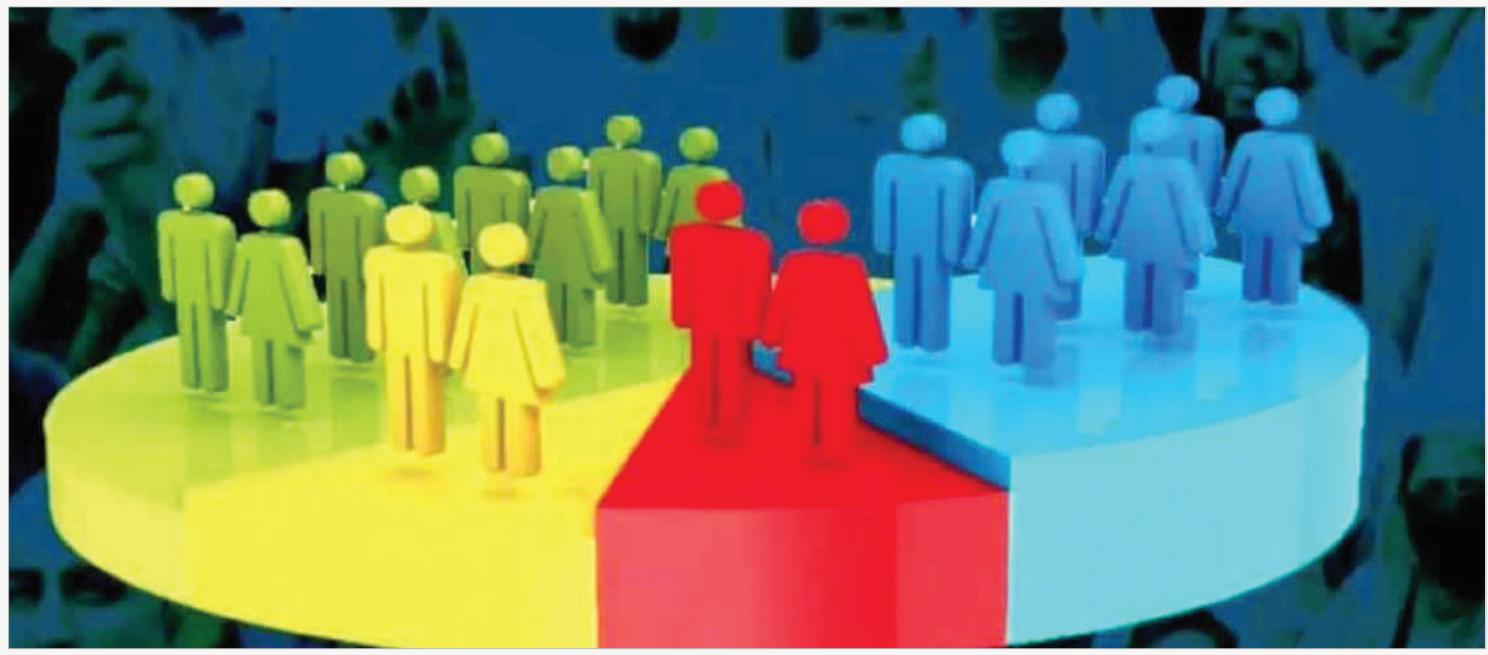
जाति के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल

- » राहुल पर अनुराग की टिप्पणी के बहाने सियासत
 - » कांग्रेस व सहयोगियों को मिला अचूक हथियार
 - » भाजपा ने भी कसी कमर बोली- बांटना चाहता विपक्ष
 - » जाति सामाजिक धृवीकरण का औजार
- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आजकल जाति को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ। अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जाति पूछने पर भाजपा व इंडिया गढ़बंधन के बीच वार-पलटवार जारी है। दरअसल भाजपा नेता ने लोकसभा में कहा कि जो लोग जातीय जनगणना करवा रहे हैं वह अपनी जाति नहीं जानते हैं। अनुराग के भाषण का पीएम मोदी ने समर्थन किया। हालांकि बहुत नेता ठाकुर के बयान की आलोचना कर रहे हैं। पर कुल मिलाकर जातीय या धार्मिक आरक्षण को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे जाने की दरकार है, न कि नकारात्मक तौर पर।

कांग्रेस की गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत में जाति और धर्म को लेकर जितने भी कानून बनाए गए, वो सब अंतर्विरोधाभावों से भरे पड़े हैं। वैदिक या सनातन सभ्यता-संस्कृति में जो जाति कार्यकृत जनसमूह की कार्यदक्षता की निशानी समझी जाती थी और राष्ट्रीय उत्पादकता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती आई थी, वही जब लोकतांत्रिक या संवैधानिक सभ्यता-संस्कृति में व्यापक विवाद का वाहक बनकर दिन-प्रतिदिन अनुत्पादक प्रतीत होने लगे, तो देश व समाज के प्रबुद्ध लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। इसलिए आज संसद में जाति के सवाल पर भाजपा नीति एनडीए और कांग्रेस नीति इंडिया ब्लॉक के बीच जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, उसके पीछे के राजनीतिक मायने को समझने और आम लोगों को समझाने की ज़रूरत है।

राजनीतिक दलों के लिए जाति अब सामाजिक ध्वनीकरण का औजार और सियासी गोलबंदी का हथियार बन चुकी है, इसलिए उसे सकारात्मक नजरिए से देखे जाने की ज़रूरत है, न कि नकारात्मक तरीके से। हाँ, अब जाति के परिषेक्ष्य में वह मुद्दा उठाने की ज़रूरत है, जिससे राजनीतिक दल और उसके चतुरसुज्ञान नेता अब तक बचते आए हैं। जैसे- साधुओं की जाति, वर्णसंकर लोगों की जाति और अंतरधार्मिक विवाह रचाने वाले लोगों और उनकी संततियों के धर्म का मुद्दा आदि सबसे अहम है। जातीय या धार्मिक आरक्षण को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे जाने की दरकार है, न कि नकारात्मक तौर पर। कांग्रेस की गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत में जाति और धर्म को लेकर जितने भी कानून बनाए गए, वो सब अंतर्विरोधाभावों से भरे पड़े हैं। जिसकी वजह से उनमें स्पष्टता का अभाव तो है ही, लोकतंत्र की मूल भावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी नदारत है। इस स्थिति के लिए हमारे राजनेता और नौकरशाह दोनों ही जिम्मेदार हैं। लेकिन इस स्थिति को बदलने का साहस किसी भी राजनीतिक दल में नहीं दिखा, जिससे राष्ट्रीय हित और पेशेवर गुणवत्ता गहरे तक प्रभावित होती आई है जिससे वैश्विक मुकाबले में भारत पछड़ता चला आया।



पहले भी राहुल उठा चुके हैं यह मुद्दा

चौहावा, संसद में राहुल गांधी के जातीय जनगणना के निक्र के बाद से जो ताजा बहस थुल हुई है, वो कोई नया मामला नहीं है। बल्कि 2023 में संसद के विशेष सत्र में महिला बिल पेश किये जाते तक राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण की मांग उठाई थी और उसके बाद से ही सोशल मीडिया के जरिये जातीय जनगणना की मांग करने लगे। बाद में कांग्रेस की कार्यकारिणी में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, जिसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान वो सता में आगे पर जातीय जनगणना का वादा भी करते रहे। विधानसभा

युनाव में राहुल गांधी के चुनावी वाटे का कोई असर नहीं दिखा, लेकिन लोकसभा युनाव में विपक्ष को जबरदस्त फायदा हुआ। इसलिए अब उसे आगे भी मुनाने की तैयारी चल रही है। अभी हाल ही में महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण में

ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलाई और जेट-मंत्र पर धरना-प्रदर्शन भी की। जिससे कांग्रेस की चाल समझी जा सकती है। वह पीएम मोदी की उनके ओबीसी मुद्दे पर ही बैकपूट पर ले जाना चाहती है। बहरहाल, यह तो मालूम नहीं कि बीजेपी के ट्यूनीटिकार इस बात को किंतुना समझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी

जातीय राजनीति में हट से ज्यादा फायदा देख रहे हैं। पहला फायदा यह है कि राहुल गांधी बड़े आराम से बीजेपी की नीरी संसद में धोर रहे हैं। दूसरा फायदा यह कि जातीय राजनीति के बहाने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनत दल जैसे राजनीतिक दलों का कांग्रेस को मजबूत स्पोर्ट मिल रहा है। तीसरा फायदा यह कि ऐसा नैरेटिव सेट करके राहुल गांधी पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वाल में जगह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस से मुहू मोड़ घुके ओबीसी व दलित तबके को फिर से पार्टी से जोगा जा सके।

बिहार में तेजस्वी ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन



बिहार में तेजस्वी यादव ने ओबीसी आरक्षण को नीरी अनुसूची का मामला उठाया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर धेरा। उन्होंने

मनोज झा की ओर से संसद में उठाए सवाल पर केंद्र के जवाब का विरोध किया। तेजस्वी यादव ने कहा, मनोज झा के सवाल का जो जवाब केंद्र की तरफ से दिया गया है। वह चौकाने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र की ओर से ऐसे ही जवाब की आशंका थी। पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीजेपी और केंद्र पर बिहार में हुई जाति आधारित जनगणना में बीजेपी पर अड़गा लगाने का आरोप लगाया। इससे पहले लोक सभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव यही बात कह बीजेपी पर हमलावर थे। उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर जातिगत जनगणना का विरोध करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा- 'हमारे प्रस्ताव पर ही सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया था।' तेजस्वी यादव ने कहा कि हमलोग शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। हालांकि बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव के इस आरोप का खड़ा कर रही है।

बीजेपी ओबीसी आरक्षण को नीरी अनुसूची में नहीं डालना चाहती

तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो ओबीसी आरक्षण को नीरी अनुसूची में नहीं डालना चाहती है। ओबीसी आरक्षण को नीरी अनुसूची में डलवाने की मांग रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार और केंद्र दोनों में ही एनडीए की सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही नीरी चाहते हैं कि बजाए गए आरक्षण को नीरी अनुसूची में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि नीरी अनुसूची में शामिल करने का काम केंद्र सरकार का है।

आरक्षण जाति-धर्म-भाषा नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर हो

साथ ही कठिनपय संवैधानिक/कानूनी कमियों को दूर किया जाना चाहिए, ताकि कभी भारतीय समाज को माला की तरह जोड़ने वाली जाति प्रथा आरक्षण उत्प्रेरित सामाजिक टूट की वजह न बन जाये। जैसा कि महसूस किया जा रहा है। इसलिए आरक्षण के आधार को जाति-धर्म-भाषा नहीं बल्कि आर्थिक आधार का किया जाना चाहिए, इसे रोटेशनल बनाकर सबको लाभान्वित किया जाना चाहिए, जो न्यायिक तर्क/वितर्क के महेनजर आसान नहीं लगता है।

बीजेपी ने विपक्ष को घेरा



बीजेपी भी जातीय जनगणना मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर देश में अराजकता भटकाने का आरोप लगाया। वहीं, भाजपा सांसद अरुण गोविल ने भी राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाया है। मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने यही बात कहा कि राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहना अजीब सा है। मुझे समझ नहीं आता कि वह बात को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से समझते हैं क्योंकि वह बात को कहीं और ले जाते हैं। वह कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कहते कुछ

जाति-जाति करती रहती है। कांग्रेस ने जाति पूछ-पूछकर देश को बांटने की साजिश की है और जब सदन में जाति की बात हुई तो राहुल गांधी हंगामा कर रहे हैं। इन लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची हुई है। ये देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी को किसने हक दिया कि वह सबसे जाति के बारे में नहीं पूछ और उनसे कोई उनकी जाति के बारे में नहीं पूछ और सकता। ये गंभीर मामला है। हम देश को टूटने नहीं देंगे, हम देश को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे।



Sanjay Sharma

 editor.sanjaysharma

 @Editor_Sanjay

जिद... सच की

छात्रों को मिल सकेगा जल्द इंसाफ !

दिल्ली में हुए कोविंग हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है। उम्मीद किया जाना चाहिए कि अब पीड़ितों को जल्द न्याय मिल जाए। दरअसल, देश की राजधानी में आईएएस बनने की आकांक्षा लेकर आए तीन स्टूडेंट्स की जिन हालात में मौत हुई, वह दुखद तो है ही, शर्मनाक भी है। इस घटना ने राष्ट्रीय राजधानी में इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेटरेंस से जुड़े तमाम विभागों और उनके कर्मचारियों पर ही नहीं, इनके संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी संभाल रहे राजनीतिक नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की गंभीरता ने स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व को जैसे नींद से जगाया। न केवल धड़ाधड़ कई गिरफ्तारियां कर ली गई बल्कि कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ बख्खास्तगी और निलंबन जैसे कदम उठाते हुए घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के आदेश भी दे दिए गए। संसद में भी यह मामला गूंजा। आ हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं कम हों।

गौर करने की बात यह है कि इस दुखद घटना को अंजाम देने वाले हालात न तो नए हैं और न ही ऊपर से नीचे तक सरकारी तंत्र का कोई भी हिस्सा इनसे अनजान है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सबको पहले से यह सब पढ़ा था, तो समय रहते कर्वाई क्यों नहीं हुई और यह भी कि क्या गारंटी है, कुछ समय बाद फिर सबकुछ पहले जैसा ही नहीं हो जाएगा। हालांकि घटना में मारे गए तीनों छात्रों की याद में उनके नाम पर चार पुस्तकालय बनाए जाने की घोषणा दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने की। हालांकि इससे जान की क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती लेकिन छात्रों के लिए सार्वजनिक पढ़ने की जगहों को बेहतर बनाने की कोशिश उन छात्रों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं सरकार ने कोविंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का फैसला लिया है। इसमें छात्रों के सुखाव भी शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने छात्रों के समर्थन में सङ्कर से लेकर संसद तक आवाज उठाई आई है और आगे भी उतारी रहेगी। इस दौरान छात्रों ने इस हादसे के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं दिल्ली सरकार और एमसीडी इस हादसे में मृतक छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी बात की है। यही इस पूरी घटना का सबसे गंभीर पहलू है और इसी बिंदु पर हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं पिलता। घटना के बाद एक-दूसरे पर दोष मढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया, वह भी निराश करता है। हालांकि अदालती हस्तक्षेप से इस तरह की घटनाओं के मामले में सख्ती दिखाई देगी जो आने वाले में इन घटनाओं पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

ਪੁਣਰਜਨ

एक आम भारतीय विश्लेषक से पूछेंगे कि मुहम्मद दीफ कौन था? तो शायद वो न मैं सिर हिला दे। लेकिन गुरुवार को सुबह-सुबह इस्साइली अखबारों की हेडलाइन मुहम्मद दीफ के मारे जाने की खबर से सनसनी पैदा कर रही थी। हमास की एक सैन्य शाखा इजदीन अल कसम ब्रिगेड के प्रमुख मुहम्मद दीफ के मारे जाने की खबर को 13 जुलाई से दबाये रखने की जरूरत क्या थी? दीफ को 13 जुलाई, 2024 को खान यूनिस इलाके में निशाना बनाया गया था। सेना ने खान यूनिस के हमले में एक और हमास कमांडर राफा सलामेह की मौत की पुष्टि की, लेकिन तब 'आईडीएफ' ने कहा था कि उसके पास मुहम्मद दीफ के बारे में अंतिम जानकारी नहीं है। इस्माइल हानिया पर हमले से पहले बेरूत के दक्षिणी उपनगर में मंगलवार को हिंजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर फौद शुक्र की मौत हो गई।

इस्साइल का कहना है कि वह गोलान हाइट्स के मजदल शम्स शहर में एक फुटबॉल मैदान पर मिसाइल हमले के लिए जिम्मेदार था, जिसमें 12 बच्चे मारे गए थे। हालांकि हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि यह आतंकी समूह द्वारा किया गया था। गत 7 अक्टूबर, 2023 के हमले में इस्साइली खुफिया एजेंसियों का जो मोरल डाउन था, वो अब फिर से ऊँचा हो चुका है। फौद, दीप और हानिया, इन तीनों के मारे जाने की खबर टाइमिंग देखिये। क्या यह सब इसलिए है कि इस्साइल की जासूसी संस्था 'शिन बेत', जिसे हिब्रू में 'शबाक'

हानिया के बाद हमास की दिशा-दशा का प्रश्न

नाम से जाना जाता है, को श्रेय दिया जा सके? शिन बेत के साथ-साथ आईडीएफ (इस्साइली डिफेंस फोर्स) और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जय-जयकार इस समय पूरे देश में हो रही है। हिजबुल्लाह और हमास के वरिष्ठ अधिकारियों की हत्याओं की सफलता के बावजूद, 115 इस्साइली बधकों की रिहाई को लेकर सबकी सांसें थमी हुई हैं। ये लोग हमास द्वारा गाजा पट्टी में 300 दिनों से बंधक बनाए गए हैं, जिनका छूटना अब भी अनिश्चित-सा है।

दीप की मौत का उदारवादी 'यिसरेल बेयटेनू' के प्रमुख एविगडोर लिबरमैन ने भी स्वागत किया है, जिन्होंने ट्वीट किया कि '7 अक्टूबर, 2023 को यहूदियों का कल्त्तोआम, बलात्कार और अपहरण करने वाले उन धृषित आतंकवादियों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनमें से कोई भी प्राकृतिक मौत न मरे।' रक्षा मंत्री योआव गैलेट का कहना है कि हमास के सैन्य कमांडर मुहम्मद दीप की हत्या की पुष्टि आतंकवादी समूह के खात्मे की दिशा में एक 'बड़ा कदम' है। लेकिन सबसे



बड़ा सवाल यह है कि ईरान हानिया और हिजबुल्लाह नेता की मौत का बदला लेगा ? ईरान के पश्चिमी मित्र सर्वोच्च नेता को सॉफ्ट करने में लगे हुए हैं। जो लोग हमास को करीब से जानते हैं, उनका दावा है कि हानिया सिर्फ हथी के दांत जैसे प्रतीकात्मक व्यक्ति थे। हमास में महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले व्यक्ति याह्वा सिनवार हैं। डॉ. माइकल मिल्शाटाइन का मानना है कि हानिया की मौत से हमास दबाव में है, लेकिन उसका सफाया एकदम से हो जाये, यह संभव नहीं।

मिल्शटाइन ने कहा, 'सिनवार हनिया को तुच्छ समझते हैं। सिनवार अक्सर कहा करते थे, 'ये सेन्य अनुभव के बिना सूट पहने हुए लोग थे, जिन्होंने हमारी तरह जेल में कष्ट नहीं झेले।' मिल्शटाइन बोलते हैं, 'हनिया का बाहरी दुनिया के लोगों से मिलना-जुलना, बयानबाजी चलता रहता था, लेकिन हमास का रिमोट कंट्रोल सिनवार के पास था। हनिया वास्तव में वह व्यक्ति नहीं थे जो जमीनी लड़ाई निर्धारित करते थे। हमास में अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति याद्या सिनवार ही रहा है, हनिया नहीं।' हनिया का दबाव जिस तरह

स्टीक जनसंख्या आंकड़ों में विकास की तस्वीर

सतीश मेहरा

जनसांख्यिकीय आंकड़े और सर्वेक्षण ही सरकार की योजनाओं का आधार हैं। जनगणना और आंकड़ों के बिना कल्याणकारी योजनाएं तैयार करना और उनका लाभ अंतिम पर्यावरण में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना 'हवा में तीर चलाने जैसा

आज 2011 की जनसंख्या के अनुसार ही 81 करोड़ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 2021 में या इसके बाद जनगणना की जाती है तो लाभार्थियों का आंकड़ा बढ़ना तय है। इस बारे में सरकार की क्या मंशा है, यह तो सरकार ही बेहतर बता सकती है।

को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए जनसार्विकीय आंकड़े निहायत जरूरी हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर क्षेत्र को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले और जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटें बांटी जाएं। आगामी 2026 के बाद देश में जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन भी किया जाना है। यह परिसीमन जनसंख्या के आधार पर



होगा क्योंकि परिसीमन के दौरान आरक्षित सीटों को बढ़ाया जाएगा। इससे यह पता चल पाएगा कि किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज्यादा है। इसी आधार पर सीटें आरक्षित होंगी। इतना ही नहीं परिसीमन के बाद महिला आरक्षण एक्ट-2023 के तहत महिलाओं के लिए भी एक-तिहाई लोकसभा और विधानसभा की सीट आरक्षित की जानी है।

देश में जनगणना का पुराना इतिहास है। 143 वर्ष पहले 1881 में जनगणना शुरू की गई थी। उसके बाद हर 10 साल में जनगणना करवाई जा रही है। दुनिया में कोविड के चलते भारत सहित अधिकतर देशों में जनगणना का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, लेकिन कोविड के बाद 100 से भी अधिक देश जनगणना करवा चुके हैं। अब भारत में भी जनगणना का इंतजार है। निःसंदेह, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास सटीक आंकड़े होंगे तो बेहतरीन योजनाएं तैयार होंगी।

संगठन पर था, उससे सिनवार ने राहत की सांस ली होगी, ऐसा कुछ विश्लेषकों का मानना है। मिल्ट्याइन बोलते हैं, ‘मुझे नहीं लगता कि सिनवार ने शैंपेन का गिलास उठाया होगा, लेकिन उनके लिए काम करने का माहौल और भी आरामदायक हो गया। हानिया ने जिंदा रहते उनके लिए कोई चुनौती नहीं पेश की, लेकिन बाधा का अहसास बना रहता था। कल गाजा में एक पत्रकार से मेरी बातचीत हुई, जिसने कहा कि हत्या के बाद गाजा और दोहा के बीच की दरारें काफी बढ़ गई हैं; इस पर नजर रखना आवश्यक है।’ गाजा की लीडरशिप और उनके कमांडर क्या दोहा में निर्वासित हमास नेताओं को खटकते थे? इस सवाल का उत्तर आने वाले समय में मिलेगा।

लेकिन एक बात तो है कि हमास के राजनीतिक व्यूहों के प्रमुख इस्माइल हानिया ने गाजा पर अपनी पकड़ बनाये रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमास के संस्थापक अहमद यासीन 1992 में लेबानान में भूमिगत हो गए थे, जहां 2004 में उनकी हत्या होने तक हानिया साये की तरह उनके साथ रहे। वर्ष 2006 में, उन्हें फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री चुना गया, और 2007 में, जब हमास ने तख्तापलट करके गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया, तो वे गाजा के वास्तविक शासक बन गए। अहमद यासीन के उत्तराधिकारी अब्देल अजीज अल-रंतिसी की हत्या के बाद हमास को नेतृत्व देने का अवसर उन्हें मिला था। वर्ष 2017 में, उन्हें हमास के राजनीतिक व्यूहों का प्रमुख चुना गया। वे कठर चले गए। हानिया ने खालिद मशाल का स्थान लिया, जिन्होंने लगभग दो दशकों तक इस पद पर कार्य किया था। अप्रैल, 2024 में इस्राइल ने गाजा शहर में हानिया के तीन बेटों और उनके तीन पोते-पोतियों की हत्या कर दी थी।

ਬਾਲੀਕੁਡ

ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ

**ਬੱਲੀਵੁਡ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀਂਦੇ
ਕੈਂਕੇ ਬਣਾਨਾ ਹੈ : ਅਲਲ੍ਹੁ ਅਜੁਨ**



ੴ

हिं दी फिल्म इंडरस्ट्री पिछले कुछ साल से बॉक्स ऑफिस पर खासा कमाल नहीं दिखा पा रही है। अगर देखा जाए तो कोरोना काल के बाद से फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेकशन में डगमगाहट देखने को मिलनी शुरू हुई थी। कोविड 19 के बाद जब थिएटर्स खुले तो हिंदी फिल्में रिलीज तो हुई पर पलौंप रहीं। वहीं दूसरी तरफ साउथ सिनेमा में कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ करमाई की। इसी के साथ बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बीच मुकाबला शुरू होता दिखा। बॉलीवुड बनाम साउथ की बहस काफी समय से सुर्खियों में है जिसपर अब दो फिल्मी जगत से जुड़े कलाकारों ने अपनी राय रखी है। बॉलीवुड को कई शानदार फिल्में देने वाले निर्देशक निखिल आडवाणी ने हाल ही में अल्लू अर्जुन के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में जिक्र किया। निर्देशक ने बताया कि पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्मों में किस चीज को सबसे बड़ी कमी मानते हैं। दरअसल, निखिल आडवाणी ने हाल ही में मिडिया के साथ बातचीत में अल्लू अर्जुन के साथ हुई बातचीत के बारे में खुलासा किया। निखिल ने बताया कि उनकी एक बार अल्लू अर्जुन मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान दोनों एक फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। उस समय अल्लू अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और कहा था कि क्या वो जानते हैं कि बॉलीवुड के साथ परेशानी क्या है? साउथ एक्टर ने आगे इसके जवाब में कहा था कि हिंदी फिल्म इंडरस्ट्री भूल गई है कि हीरोज कैसे बनता है। इंटरव्यू में निखिल ने अल्लू अर्जुन की बात को सही से समझाते हुए बताया कि लोगों को लगता है कि साउथ सिनेमा पौराणिक कथा और अन्य चीजों में सिमटा हुआ है। लेकिन, डायरेक्टर का मानना है कि साउथ के मेकर्स कोर इमोशन को समझते हैं और उसी को लेकर चलते हैं।

અજબ-ગજબ

इसे कहा जाता है सहेलियों की बाड़ी

उदयपुर की ऐसी बाड़ी जहाँ पुरुषों का जाना था मना

उदयपुर। उदयपुर में घूमने की बहुत-सी जगहें हैं लेकिन सहेलियाँ की बाड़ी अलग है। महारानी के लिए राजा ने इस बाड़ी को बनवाया था। सालों की मेहनत के बाद इस बाड़ी को तैयार किया गया। बेहद खुबसूरत वास्तुकला और हरियाली यहाँ देखने के लिए मिलती है। इस बाड़ी को तैयार करने के लिए उस वक्त ऐसा तकनीक का इस्तेमाल हुआ था कि आज भी लोग देख कर हैरान रह जाते हैं। इस आर्टिकल में जानें इस बाड़ी से जुड़ी हर-छोटी बड़ी बात।

दूर गाइड नारायण साली बताते हैं कि सहेलियों की बाड़ी को महाराणा संजय सिंह ने 1710-1734 में बनवाया था। इस बाड़ी को महारानी और उनकी 48 सहेलियों के लिए बनवाया गया था इसलिए इसे 'सहेलियों की बाड़ी' कहा जाता है। लोग इसे मेडन्स गार्डन के नाम से भी जानते हैं। बाड़ी में बांग, फटारे, मर्बल स्टंभ और संगमरमर का इस्तमाल देखने के लिए भिलता है। इसका डिजाइन हिन्दू और मुघल वास्तुकला से बना है। यह गार्डन लगभग 6.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें एक गार्डन में एक संग्रहालय भी है, जहां इतिहास से जुड़ी दिलचस्प जानकारी मिलती है।

सहेलियों की बाड़ी में कई खूबसूरत फट्टारे हैं, जिन पर शानदार और यूनीक डिजाइन देखने



के लिए मिलते हैं। इस वजह से बाड़ी हमेशा ताजगी का एहसास देती है। यहां के लोटस पूल भी हैं, जो हरी-भरी हरियाली से पिरा है और संगमरमर से बना है। इस बाड़ी में संगमरमर के पत्थर से ढेर सारे हाथी भी बने हैं, जो आपको बाड़ी के किनारों पर लगे दिखेंगे। बाड़ी में छोटे-बड़े ढेर सारे आंगन हैं, जहां कमाल की वासुकुला फूल, पौधे, पेड़ और झाड़ियाँ से घिरी दिखेंगी। सहेलियां की बाड़ी में महारानी अपनी सहेलियों के साथ समय बिताती थीं। इस दौरान सभी एक साथ मिलकर बागवानी करती थीं। सभी एक दूसरे की गाने और कविता सुनाया करते थे। मजा करते के लिए चूड़ी बाजी जैसे गेम्स भी महारानी अपनी सहेलियों के साथ खेलती थीं। उस वक्त पुरुष इस बाड़ी में नहीं जा सकते थे। सहेलियों की बाड़ी का जादुई गार्डन लोगों को बहुत

आर्किष्ट करता है। इस गार्डन के पास ताली
बजाते ही फव्वारे चल जाते हैं। जब गार्डन के पास
चलते हैं तो चारों ओर पानी बहने लगता है। सालों
पहले इस फव्वारें को बनाते वक्त विशेष तकनीक
का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से लोगों ने
इसका नाम जादुई गार्डन रखा।

इस जगह एक म्यूजियम भी बना है, जहां ऐतिहासिक और प्राचीन चीजें देखने के लिए मिलती हैं। कला, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक वस्तुएं और पेटिंग जैसी चीजें म्यूजियम में मौजूद हैं। सालों पुरानी जीवनशैली से जुड़ी वस्तुएं भी इस म्यूजियम में आप देख सकते हैं। हर साल में एक बार सहेलियों की बाड़ी में मेला लगता है। हरियाली अमावस्या पर लगने वाले इस मेले में पुरुष नहीं जा सकते। खरीदारी के लिए, खेलकूद और मजेदार एक्टिविटी मेले के दौरान लगती हैं, जिनका महिलाएं आनंद उठाती हैं। सहेलियों की बाड़ी में जाने की टिकट लगती है। आपको 20 रुपये की टिकट लेनी होगी। वहीं, अगर विदेशी लोगों यहां जा रहे हैं तो उन्हें 100 रुपये की टिकट लेनी होगी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के पंचवटी में बनी है। उदयपुर तक आप ट्रेन या बस पर पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचने के बाद सहेलियों की बाड़ी तक जाने के लिए टैक्सी या बस से ट्रैवल कर सकते हैं।

सिटाडेल के टीजर में वरुण धवन और सामंथा के एकशन ने बढ़ाया उत्साह

ਬੋਲੀਕੁਡ | ਗਪਥਾ

गापशाप

7 नवंबर को इलीज
होगी सीरीज

सिटाडेल हनी बनी मैं सिंकंदर खेर,
साकिब सालीम, सोहम मजुमदार,
शिवकांत परिहार और केशवी
मजुमदार जैसे सितारे भी 3 अहम
किरदारों में नजर आने वाले हैं। यह
सीरीज 7 नवंबर को प्राइम वीडियो
पर भारत और दुनिया भर के
240 से भी ज्यादा देशों और क्षेत्रों
में प्रीमियर के लिए तैयार है।

सिचुएशन के हिसाब से इस पर
बिल्कुल फिट भी बैठ रहा है। टीजर में
वरुण और सामंथा के अलावा एकटर
केके मेनन की भी झालक देखने को
मिली है। हालांकि, उनका
किरदार क्या है इसका
खुलासा तो वक्त
के साथ ही हो
पाएगा।

प्रोजेक्ट का प्रमोशन भी हो सकता है। दूसरी ओर फैस यह जानने के लिए बताव हैं कि शिव की जिंदगी में किस लड़की की एंट्री हुई है। वही, फिलहाल शिव की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

गैरतलब है कि कुछ समय पहले ही शिव ने अपनी झीम गर्ल को लेकर कहा था, मुझे बस अपने लिए एक ईमानदार लड़की चाहिए, जो रिश्तों को निभा सके। मुझे लुकस को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए बस 10-15 दिनों में एक बार सूट-सलवार पहनकर बिंदी लगा लिया करे। इतना ही नहीं, शिव खुद को बहुत अधिकार जताने वाला और इमोशनल पर्सनल मानते हैं।

1000 बच्चों का बाप है 43 साल का शहव्य, अब बाप बनने पर इन्हें देना होगा 91 लाख का जुर्माना!



किसी भी आदमी के लिए पिता बनने का एहसास बेहद खास होता है। जब एक पुरुष, पहली बार अपनी संतान को गोद में लेता है, तो वो कई तरह की भावनाओं को अपने अंदर महसूस करता है। पर नीदरलैंड का एक आदमी इस एहसास को इतनी बार महसूस कर चुका है, कि अब शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता! जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं, वो 43 साल का है और लगभग 1000 बच्चों का बाप बन चुका है। उसने इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए हैं कि अब आलम ये है कि अगर उसने एक और बच्चा पैदा किया, तो उसे 91 लाख रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।

जॉनथन मेयर पर नेटप्रिलक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस शख्स के काफ़ी चर्चे हैं। पर वयों, इस शख्स ने ऐसा क्या किया है? दरअसल, जॉनथन 1-2 नहीं, बल्कि 1000 बच्चों के पिता है। उन्हें ठीक-ठीक याद भी नहीं है, हालांकि, वो अंदाजा लगाते हैं कि उनके करीब 1000 बच्चे तो अलग-अलग देशों में मौजूद हैं। नीदलैंड के 43 वर्षीय जॉनथन ने डेली मेल से बात करते हुए कहा था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ सार्थक और अर्थपूर्ण करना चाहता था, इस जहज से उसने इस तरह समाज की सेवा करने का फैसला किया। असल में जॉनथन एक स्पर्म डोनर रह चुके हैं जो अब रिटायर हो गए हैं। उन्होंने अलग-अलग देशों में रहने वाले सैकड़ों कपल्स को स्पर्म डोनेट किया, जिसकी मदद से वो माता-पिता बन सके। पर अब बच्चों को संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, कि माता-पिता को ये डर लगने लगा है कि आगे लकर कहीं उनके बच्चे, अंजाने में अपने ही सौतेले भाई-बहनों के साथ रिश्ते में न आ जाएं। जॉनथन एक पार्ट टाइम म्यूजिशियन और यूट्यूबर हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने कई बच्चों को मिल चुके हैं। वो सभी खुश नजर आते हैं। उनमें से कई अपने सौतेले भाई-बहनों से मिल चुके हैं और उनके साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके डोनर बच्चे जानते हैं कि वो उनके पिता हैं, वो जॉनथन का नाम जानते हैं। इसके अलावा जॉनथन ने ही बड़े ध्यान से स्पर्म डोनेट करने के लिए माता-पिता का चरण किया है। उनका दावा है कि वो एक ओपन आइडेंटीटी डोनर है। उनका दावा है कि इस तरह उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे इनक्रीडिंग से बच सकें। जॉनथन जब 26 साल के थे, तब से स्पर्म डोनेशन कर रहे हैं। उनका आंकलन है कि उनके करीब 550 बच्चे हैं, हालांकि, लोगों का मानना है कि वो 1000 तक हैं। एक बार तो उन्होंने एक महिला को स्पर्म डोनेट करने के लिए ट्रिडिशनल तरीका अपनाया, यानी उस महिला से संबंध स्थापित कर के उसे स्पर्म डोनेट किया था। द सन के अनुसार 30 अगर जॉनथन 1 और बच्चा करते हैं, तो उन्हें जुमाने के रूप में 91 लाख रुपये से ज्यादा बुकाने पड़ेंगे।

आउटसोर्सिंग एजेंसी बना एनटीए : जयराम

» कांग्रेस ने एनटीए चीफ पर उठाए सवाल

» कहा- मप्र में अध्यक्ष रहते संदिग्ध रहा इनका रिकॉर्ड

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक केस पर जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) और इसके चीफ पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जयराम रमेश ने एकस पर पोस्ट में लिखा कि ऐसा लगता है एनटीए का एकमात्र काम आउटसोर्सिंग करना है। इसके अध्यक्ष का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रमुख के रूप में बेहद संदिग्ध रिकॉर्ड था। जयराम रमेश ने टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष के एक ट्रीटी पर रिएक्ट करते हुए ये टिप्पणी की।

जयराम रमेश ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब बीते मई महीने में ही एनटीए चेयरमैन की जिम्मेदारी प्रदीप सिंह खरोला को सौंपी गई थी। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एकस पर लेटर शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया कि मैंने शिक्षा मंत्रालय और

टीएमसी सांसद के लेटर पर एमेश ने किया रिएक्ट

देश में मुन्ना भाई डॉक्टर हो रहे तैयार : चढ़ा

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक पत्र लिखा है। इसमें मैंने कुछ सवाल उठाए हैं। मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से पूछा है कि आखिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए), जो नीट सहित 17 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करती है, इसकी वेबसाइट अपने बारे में इतनी कम जानकारी क्यों देती है?



नीट-यूजीसी 2024 परीक्षा में हुई गड़बाड़ी को लेकर अमन आमनी पार्टी के सांसद राधव छड़ा ने राज्यसभा में मोटी सरकार के खिलाफ उन्होंने मारवीनी शिक्षा प्रणाली से जुड़ी समस्याओं पर अपनी बात रखी। आप सांसद ने कहा, लाल्हों की नीट अवृत्ती अनियन्त्रिताओं के कारण दुखी हैं। अग्र ऐसी घटनाएं जारी रहीं तो हमें मुन्ना भाई डॉक्टर देखने को

मिलेगे। सरकार को नीट पेपर लीक की जांच करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को देतिर करना चाहिए। राधव छड़ा ने आगे कहा, बिंगड़ी शिक्षा व्यवस्था का संकट हमारे देश को प्रभावित कर रहा है। यह व्यवस्था की बाजे देश का देश को नीचे रख रहा है।

करती थी, लेकिन आज यह एक युद्ध का दैदान बन गई है, जहां हमारे बच्चे जान या अधिकार के लिए नहीं, बल्कि

अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप सांसद ने कहा कि बहुत कम उम्र से ही हमारे लोगों को कहीं न खात्म होने वाली दौड़ में धकेल दिया जाता है और कुछ नवा लोगों की इच्छा एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के दबाव से नीचे दब जाती है, वज्रोंके बच्चों में सीखने की जिजासा को फ़लने-फ़लूने देने की जगह हमारी शिक्षा प्रणाली उन्हें ये सिखा रही है कि उनकी योग्यता सिर्फ उनके द्वारा प्राप्त नहीं, बोइंग द्वारा प्राप्त होती है।

प्रदीप सिंह खरोला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट पेपर लीक मामले पर घमासान के बाद तकालीन एनटीए

योग सुनाए कुमार महीने में हटा दिया गया था। उनकी जगह पर एनटीए का चेयरमैन प्रदीप सिंह खरोला नीट गई। खरोला कन्फिकेशन से 1965 बैच के आईएससी अधिकारी है। 1961 में जन्मा जन्म हुआ। खरोला नागरिक उद्ययन नंगलालय के केंटेक्टी और उससे पहले पर्टिटन मंत्रालय के निदेशक नीट युद्ध हुए हैं। वो खीरीगढ़ लोकसेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के भी अध्यक्ष हैं। आईएससी प्रदीप सिंह खरोला को ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुस्तकार मिल बुका है।

सागरिका घोष ने धर्मेंद्र प्रधान को लिखा पत्र

सागरिका घोष ने शिक्षा मंत्रालय को लिखे पत्र में ये पूछा कि आखिर लोड के सभी सदस्य कौन है? अधिकारी कौन है? एनटीए की वार्षिक रिपोर्ट कब है? ऐसे कई सवाल पूछे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य की परीक्षाओं के लिए जनता का विवास जीतने के लिए एनटीए को अपनी बेलासाइट पर अपने बारे में अधिक जानकारी देनी चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष बनाने की खबरें अफवाह : देवेंद्र फडणवीस

» बोले- यह केवल मीडिया में चर्चा है

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

मुंबई। बीजेपी जल्द ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। इस तरह की चर्चा लगातार हो रही है क्योंकि जेपी नद्दा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। जेपी नद्दा को मोदी 3.0 कैबिनेट में स्थानांश और परिवार कल्याण मंत्री के साथ-साथ रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहा है कि पार्टी अपने नए अध्यक्ष का नाम तय करने के करीब है। इस तरह का दावा किया गया था कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की उम्मीद है।

हालांकि, देवेंद्र फडणवीस ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह चर्चा मीडिया द्वारा ही शुरू की गई है। यह केवल मीडिया में चर्चा है।



वाले हफ्तों में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नई दिल्ली जा सकते हैं। मुलाकात के बाद फडणवीस परिवार को प्रधानमंत्री के साथ फोटो सेशन का भी मौका दिया गया। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि बैठक में पीएम मोदी और फडणवीस के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र फडणवीस को मुंबई से नई दिल्ली ले जाने के फैसले पर चर्चा हुई और अगले कुछ दिनों में पार्टी के भीतर की राय पर चर्चा की गई।

हालांकि, देवेंद्र फडणवीस ने इसको

दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में हुई 14 मौतों पर सियासत शुरू

» आप को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं : मनोज

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने आशा किरण शेल्टर होम में 14 की लोगों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने तत्काल मामले पर एकशन लिया है और 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं, इस मामले में भाजपा व आप में वार-पलटवार शुरू हो गया है। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, पिछले कुछ महीनों में यहां 27 मौतें हुई हैं। इसका कारण गंदा पानी, संक्रमण, तपेदिक और निमोनिया लग रहा है।

ऐसी कई खबरें मीडिया में चल रही हैं। सवाल यह है यह किसकी लापरवाही है? यह आप सरकार की आपाधिक लापरवाही है, क्योंकि यह आश्रय गृह चलाना उनका काम है। इसका मतलब है कि इसमें भ्रष्टाचार की चाहिए। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, खबरें पढ़ना मुश्किल है... आशा किरण में मानसिक रूप से विक्षिक्षण लोगों को रखा जाता है। जानकारी मिली है कि बच्चों



के ठाकुर से खाना नहीं दिया जाता। वहां अगर बच्चे बीमार पड़ जाएं तो उन्हें इलाज नहीं मिलता। आप आदमी पार्टी को अपने पद बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं। आप आदमी पार्टी जो कहती है वो करती कहां है? आप आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को बेहद दुखद स्थिति में पहुंचा दिया है। दिल्ली को बचाने के लिए ऐसे लोगों को पद से हटाना बहुत जरूरी है।

इंडिया-श्रीलंका का पहला वनडे बराबरी पर छूटा

» रोहित के अलावा नहीं चला भारत का कोई बल्लेबाज

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

पल्लेकल। क्रिसान रोहित शर्मा (58 रन) द्वारा दिलाई गई तेज शुरूआत के बावजूद भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच टाई रहा। श्रीलंका का शीर्ष क्रम भारत की सटीक गेंदबाजी के सामने चरमरा गया लेकिन सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (56 रन) और निचले क्रम में दुनिथ वेलालांगे (नाबाद 67 रन) के संयुक्त अर्धशतकों की मदद से मेजबान टीम ने आठ विकेट पर 230 रन बनाये।

इसके जवाब में पूरी भारतीय टीम



श्रीलंका के स्पिनरों के सामने 47.5 ओवर में 230 रन के स्कोर पर सिमट गई जिससे मैच टाई रहा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच अंशुमन गायकवाड़ की याद में भारतीय क्रिकेटर बांह पर काली पट्टी बांधकर खेले। गायकवाड़ का बुधवार को निधन हो गया। वह रक्त कैंसर से पीड़ित थे। श्रीलंका के स्पिनरों ने वानिंदु हसारांगा की

अगुआई में रन गति पर लगाम कसते हुए लगातार अंतराल पर विकेट झटके। हसारांगा ने 58 रन देकर तीन, क्रिस चरिथ असालांका ने 30 रन देकर तीन और दुनिथ वेलालांगे ने 39 रन देकर दो विकेट झटके। अकिला धनंजय ने 40 रन देकर दो विकेट झटके।

एक विकेट प्राप्त किया। रोहित और शुभमन गिल (16 रन) ने पहले विकेट के पास गिल के 76 गेंद में 75 रन की साझेदारी करके भारत को

भारतीय गेंदबाजों का प्रयास अच्छा रहा

भारतीय गेंदबाजों का प्रयास नीट अच्छा रहा जिन्होंने श्रीलंका बल्लेबाजों को खारिब खोलने पर जग्गा किया। मेंटिस को दुर्बे ने पगबाधा आउट किया। श्रीलंका का एक दो विकेट पर 46 रन से 27 वें ओवर में पांच विकेट पर 101 रन हो गया।

भारत के लिए अक्षर पटेल (33 रन देकर दो विकेट) और अर्पणीषंद दिवेंग (33 रन देकर दो विकेट) ने दो दो जलकि कुलदीप यादव, वारिंगटन सुदर, गोलग्नाद सिंहज और शिवक दुर्बे ने एक एक विकेट लटका।

अच्छी शुरूआत कराई। लेक

अब अहिमामऊ उजाड़ने की तैयारी !

150

मकानों पर आवास विकास
ने चरण की नोटिस

घरों को बचाने के लिए बुलडोजर
के सामने आई महिलाएं

विरोध के बाद एक हफ्ते की मोहल्लत
देकर लौटी टीम, दृश्यत में निवासी

■■■ मो. शारिक/4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राजधानी में एकबार फिर बुलडोजर ने लोगों को डरा दिया है। अबकि बार ये बुलडोजर लखनऊ के अहिमामऊ इलाके में पहुंचा था। दरअसल, शनिवार को अचानक आवास विकास की टीम बुलडोजर लेकर वहां पहुंच गई। ज्ञात हो यहां 150 मकान पर आवास विकास ने नोटिस चरण की थी। बताया गया कि यह जमीन आवास विकास अपने कब्जे में लेगा।

टीम जैसे ही इलाके में पहुंची बड़ी संख्या में महिलाएं बुलडोजर के सामने आए गई। उनके साथ इलाके के लोग भी एकत्र हो गए। आवास विकास, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति यह थी कि करीब डेढ़ घंटे के विरोध के बाद टीम को बापस जाना पड़ा। हालांकि इस दौरान आवास विकास के इंजीनियरों ने 7 दिन बाद फिर से कार्रवाई की बात की है।



सबके मकान की रजिस्ट्री और दाखिल खाइज है

यह रहने वाले स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता राजें सिंह ने बताया कि वह लोग 4 साल से यहां रहते आ रहे हैं। सबके मकान की रजिस्ट्री और दाखिल खाइज है। ऐसे में आवास विकास महज एक नोटिस चरण कर अपना दावा कैसे पेश कर सकता है? उन्होंने बताया कि इसको लेकर जब गैरके पर आए आवास विकास के इंजीनियरों से बात की गई तो कोई कागज नहीं दिया गया। एक्सीएन विशाल पाड़े और उनकी पूरी टीम को बापस जाना पड़ा।



सार्वजनिक सूचना

उत्तराखण्ड एवं निकास परिषद् द्वारा तुरंगात पालाजी के अन्तर्गत प्राम अहमामक या चरांग नं. 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1220, 1221, 1222, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180 अंतिम विधा गयी है। चरांग जलसे भी भूमि पर विस्तीर्णी भी प्रकार आवास विकास निमित्त/अधिक कामों से छोड़ जाए। अवधारणा परिवर्तन विधा के अन्तर्गत अन्यायकृत निमित्त/अधिक कामों को असत जलने की कार्रवाई भी जारी है, जिसका सम्बन्ध उत्तराखण्ड अधीनी यात्रीवाहिका/अन्यायिक निमित्त करने वाले व्यक्ति का होता है। अस्तीकरण में होने वाले व्यक्ति की सहस्री राजस्व की भीती की जाएगी।

आपको निमित्त

यह निजी प्रॉपर्टी डीलर के जमीन बेची है। वैसे यह सोसाइटी देश और बाकी भारत के खिलाफ है लेकिन लोगों के पास रजिस्ट्री और

दाखिल खाइज के पर्याप्त कागज नोगृह है। दावा किया जा रहा है कि जिन 150 मकानों को नोटिस दी गई है। उनमें सभी के पास नोटिस है।

अभियान के दौरान पुलिस की टीम में महिला कर्मचारी नहीं थीं। ऐसे में जब महिलाएं बुलडोजर के सामने आई तो उनको हटाने वाला भी कोई नहीं था।

बिना महिला पुलिस के पहुंची थी टीम इलाके के कर्मी 300 लोग आवास

विकास और पुलिस प्रशासन पर भारी पड़े। लोगों ने इस स्तर पर विरोध किया कि आवास विकास की टीम के पास पीछे हटने के लागत कोई वारा नहीं था।



तंदूर वाले होटलों पर गिरेगी गाज

प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम ने शुरू की तैयारी

» गैस आधारित तंदूर बांटने की है योजना

■■■ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सर्दी आते ही शहर का वायु गुणवत्ता सूखकांक बेहद खराब हो जाता है। इससे राजधानी का प्रदूषण लेवल भी बढ़ जाता है। इसी को रोकने के लिए नगर निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ नगर निगम शहर के होटल और रेस्टोरेंट में कोयला वाले तंदूर पर रोक लगाने जा रहा है।

वायु प्रदूषण के नियंत्रण व एनजीटी की सख्ती के बाद होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में चलने वाले तंदूर की भृत्यों पर रोक लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम तंदूर का इस्तेमाल करने वाले होटल व रेस्टोरेंट का सर्वे करा रहा है। इसके बाद होटलों के मालिकों को नोटिस जारी कर लकड़ी और कोयला आधारित तंदूर का उपयोग बंद कर इलेक्ट्रिक या एलपीजी वाले तंदूर का इस्तेमाल किए जाने के निर्देश दिए जाएंगे। पहले चरण में लालबाग व आस-पास के क्षेत्र में इसकी शुरूआत की जाएगी।

उर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) की ओर से लखनऊ शहर के वायु प्रदूषण स्रोत पर होटल और रेस्टोरेंट की 44 इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया। संस्था के अध्ययन में सामने आया है कि वायु प्रदूषण में प्रमुख स्रोतों के अलावा, होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्रों और सड़क के किनारे भोजनालयों से वातावरण में पीएम 10 और पीएम 2.5 की मात्रा बढ़ रही है। असल में होटल और रेस्टोरेंट में पारंपरिक या कोयला आधारित तंदूर का उपयोग किया जाता है। इसकी वजह से धुआं उत्पन्न होता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। नगर निगम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार तंदूर में इस्तेमाल होने वाले कोयला और लकड़ी के धुएं से प्रदूषण तो फैलता ही है, साथ ही तंदूर की रेटिंगों

में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी ज्यादा होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है लिहाजा तंदूर के बजाय अब इलेक्ट्रिक या एलपीजी आधारित गैस का उपयोग किया जाना जरूरी है।

स्वामी 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से

प्रकाशित। संपादक - संजय शर्मा, विविध सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जादी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |

RNI-UHPIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

पेरिस नहीं जा सकेंगे सीएम भगवंत मान

» हॉकी टीम की हौसलाअफजाई करने जाना चाहते थे सीएम

■■■ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान को पेरिस जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय ने अनुमति देने से इनकार करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय को शुक्रवार देर शाम यात्रा की अनुमति नहीं मिलन की सूचना मिली।

गौरतलब है कि भगवंत मान भारतीय हॉकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए पेरिस जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। पेरिश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मांगी थी, जो 4 अगस्त को हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के समर्थन करने के लिए पेरिस जाने की योजना के लिए मंजूरी नहीं दी है।

सीएम मान, जिनके पास लाल रंग का राजनीतिक पासपोर्ट है, जो अमृतौर पर बीजा प्रक्रिया में तेजी लाने की अनुमति देता है, ने हॉकी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए पेरिस की अपनी यात्रा के लिए गृह मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मांगी थी, जो 4 अगस्त को चल रहे ओलंपिक में अपना पहला क्रार्टर (एमएचएच) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लालबाग व आस-पास के क्षेत्र में इसकी शुरूआत की जाएगी।

पंजाब के लालबाग व आस-पास के क्षेत्रों के लिए उत्सुक थे, लेकिन केंद्र ने जेड+ सुरक्षा प्राप्ति के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया।

से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के होने के कारण, मान व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन दिखाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन केंद्र ने जेड+ सुरक्षा प्राप्ति के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया।

से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के होने के कारण, मान व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन दिखाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन केंद्र ने जेड+ सुरक्षा प्राप्ति के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया।

से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के होने के कारण, मान व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन दिखाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन केंद्र ने जेड+ सुरक्षा प्राप्ति के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया।

से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के होने के कारण, मान व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन दिखाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन केंद्र ने जेड+ सुरक्षा प्राप्ति के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया।

से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के होने के कारण, मान व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन दिखाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन केंद्र ने जेड+ सुरक्षा प्राप्ति के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया।

से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के होने के कारण, मान व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन दिखाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन केंद्र ने जेड+ सुरक्षा प्राप्ति के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया।

से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के होने के कारण, मान व्यक्तिगत रूप से अपना समर्थन दिखाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन केंद्र ने जेड+ सुरक्षा प्राप्ति के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया।

</div